पूरी थी बिजली, आधा था दाम !
'आप' ने लगाई थी, बिजली कंपनियों पर लगाम !!

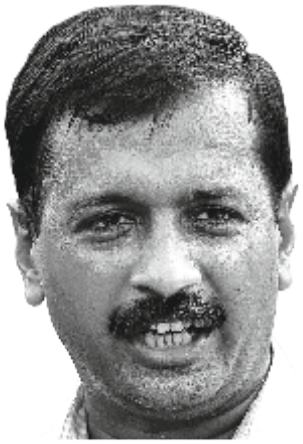

याद करो 1 फरवरी 2014 का दिन। जब दिल्ली की बिजली कंपनियों ने धमकी दी थी कि वे 10 फरवरी 2014 से दिल्ली की बिजली काट देंगे और पूरी दिल्ली अंधेरे में चली जाएगी। अरविंद केजरीवाल उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल ने तुरंत बिजली कंपनियों को चेतावनी जारी की- ''यदि आपने दिल्ली की बिजली काटी तो सरकार आपके लाइसेंस रद्द कर देगी और दिल्ली में नई बिजली कंपनियां ले आएगी।'' यह चेतावनी देकर अरविंद केजरीवाल ने तुरंत कुछ नई बिजली कंपनियों से बातचीत करना शुरू कर दिया। इस कड़ी चेतावनी ने जादू का काम किया। 8 फरवरी को बिजली कंपनियों ने कहा कि वो दिल्ली की बिजली नहीं काटेंगे।

जब से दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ है, ये देखने में आया है कि अगर बिजली कंपनियों के साथ सख़्ती न करो तो ये कंपनियां दिल्ली सरकार और दिल्लीवालों को ब्लैकमेल करती हैं।

अब जनता है त्रस्त, बिजली कंपनियां हैं मस्त, भाजपा क्यों नहीं हो रही सख़्त?

आज दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है। केन्द्र में भाजपा की सरकार है, इसीलिए दिल्ली को केन्द्र से भाजपा ही चला रही है।

पूरी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जमकर पावर कट लग रहे हैं। कई-कई घंटों तक बिजली गायब है। इसका क्या कारण है? जनता का बुरा हाल है, लेकिन मंत्रियों के यहां 24 घंटे बिजली है।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने तूफान आने के 10 दिन बाद प्रेस कॉफ्रेंस की और उसमें कहा कि दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है तो बिजली गुल क्यों हैं? पीयूष गोयल जी का कहना है कि दिल्ली में पिछले 12 साल में शीला दीक्षित सरकार के दौरान में बिजली कंपनियों ने अपने उपकरणों (जैसे खंभे, ट्रांसफार्मर, तार इत्यादि) का ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया और आधुनिकरण नहीं किया। इस वजह से दिल्ली की सारी बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। उनका कहना है कि 30 मई 2014 को जो तूफान आया था उस तूफान में कई खंभे गिर गए, कई तार टूट गए- इसे ठीक करने में 15 दिन और लगेंगे।

पीयूष गोयल जी के कहने में आधी सच्चाई है। ये बात तो ठीक है कि ये बिजली कंपनियां पिछले 12 साल से ये दिखाती रही हैं कि इन्होंने उपकरणों के मेंटेनेंस और आधुनिकरण में काफी पैसा लगाया है। इसी वजह से ये कंपनियां आज सरकार से पिछले वर्षों का घाटा मिलाकर 17 हज़ार करोड़ रुपये मांग रही है। 2010 में जब इन कंपनियों के खातों की जांच की गई तो पता चला कि इन कंपनियों ने कई झूठे बिल लगा रखे थे। उन्होंने असल में कम खर्चा किया था लेकिन कई गुना पैसे के बिल लगा रखे थे। इसका मतलब पिछले 12 साल में कांग्रेस की सरकार में ये कंपनियां धोखाधड़ी करके फर्जी घाटा दिखाती रहीं और अब 17 हज़ार करोड़ रुपये मांग रही है।

लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन 12 सालों में दिल्ली में भाजपा विपक्ष में थी, तब भाजपा ने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया? तब भाजपा ने कांग्रेस की खिंचाई क्यों नहीं की?

जनवरी के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही केजरीवाल ने कहा कि 17 हज़ार करोड़ रुपये की जांच कराई जाएगी। केजरीवाल ने CAG के ऑडिट के आदेश दे दिए। कंपनियां खूब चिल्लाईं। लेकिन अंत में उन्हें मानना पड़ा।

आज दिल्ली में बिजली की समस्या का क्या समाधान है?

आज फिर से दिल्ली की बिजली गुल करके ये बिजली कंपनियां दिल्ली के लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। इनके साथ सख़्ती करने की जरूरत है। इनकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के साथ बिजली कंपनियों ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे और नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

जिस तरह से केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के साथ सख़्ती करके उनको ठीक किया था, वैसे ही भाजपा बिजली कंपनियों के साथ सख़्ती क्यों नहीं करती? भाजपा के ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल बिजली कंपनियों की जवाबदेही तय करने की बजाय उनका बचाव करते नज़र आ रहे हैं। आखिर क्यों?

अगर बिजली कंपनियां जल्द से जल्द बिजली ठीक नहीं करतीं तो इन पर पेनल्टी लगाई जाए और जरूरत पड़े तो इनके लाइसेंस रद्द किए जाएं और नई बिजली कंपनियां लाई जाएं।

दिल्ली में बिजली सस्ती की जाए।

दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि हम दिल्ली में बिजली 50 प्रतिशत सस्ती कर देंगे। केजरीवाल ने सरकार बनने के पांच दिन के अंदर बिजली के बिल आधे कर दिए। इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वो 31 मार्च तक सब्सिडी का प्रावधान करके गए थे। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उस वक्त केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। 1 अप्रैल से बिजली के बिल फिर से दोगुने हो गए। केन्द्र में बैठी कांग्रेस की सरकार चाहती तो दिल्ली वालों को सब्सिडी देकर बिजली के बिल फिर से आधे कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अब केन्द्र में भाजपा की सरकार आई है। दिल्ली में अभी भी राष्ट्रपति शासन है। भाजपा अगर चाहे तो दिल्ली वालों को सब्सिडी देकर बिजली के बिल कम कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो वो दिल्ली में 30 प्रतिशत बिजली के बिल कम करेंगे। अब तो दिल्ली को राष्ट्रपति शासन के जरिए भाजपा ही चला रही है तो फिर वो 30 प्रतिशत बिजली के बिल कम क्यों नहीं करती?

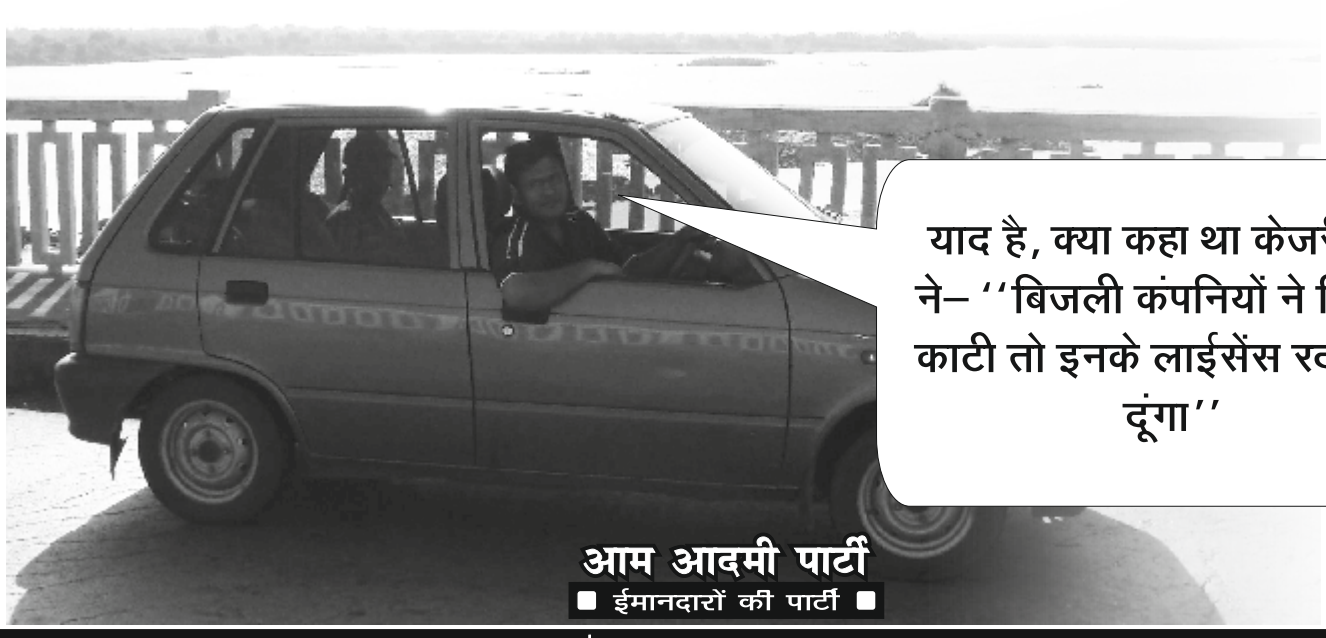

कार्यालय: ए-119, कौशांबी, ग़ाज़ियाबाद, उ0प्र0 | email: contact@aamaadmiparty | 9718500606 | www.aamaadmiparty